

		H(5)(b)	Comp., ABAS, etc.	--
		I	Pension Gratuities	
		J	Survey of land	
		L(4)(a)	Stationary	--
		L(4)(b)	Printing	
		L(4)(c)	Postage	--
		L(4)(e)	Books & Periodicals	2850
		L(4)(g)	Law charges	720400
		L(4)(h)	Telephone ch.	50
		L(4)(l)	Audit ch.	113307
		L(4)(j)	Misc.	35
		L(10)	General Election	--
		M(1)	Fix Deposit in Bank	150000
		M(2)		--
		M(3)	Repayment of loan Advance, Extra Ordinary & Debt	--
		M(4)		740
		M(5)	Deposit	
			Total expenditure -	4767174
		Total receipt -	36773354.00	
		(+) Opening Balance -	46772714.08	
		(-) Total -		83546068
		Total -	83546068.08	
		(+) Closing Balance -		35874321

**RESOLUTION:** Considered, approved and passed the monthly account for the month February and March, 2019.

**Note:** During discussion vice-president Shri umesh Kumar requested that may be written to Nagar vikas, Patna requesting for street light since lights have been given by Nagar Vikas to nearby area such as Danapur Nagar Nigam under smart city plan.

सी सं- 78 :-

सा सं- 78 :-

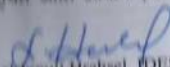
श्री सुशील कुमार सरोज से प्रतिनिधित्व, दानापुर छावनी बोर्ड के पूर्व क्लर्क दानापुर छावनी  
का दिनांक 06.03.2019 और 25.03.2019 को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का निर्णय  
सी। विदे ए. सं- 43/Defence-34/2016-SSW-1

Representation from Shri Sushil Kumar Saroj, Ex Clerk of Danapur Cantonment Board to Danapur  
Cantonment Board dated 06.03.2019 & 25.03.2019 and Decision of the National Commission for Scheduled  
Castes (NCSC) vide F.No. 43/Defence-34/2016-SSW-1


श्री सुशील कुमार सरोज, दानापुर कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व-क्लर्क, दानापुर कैंटोनमेंट बोर्ड से दिनांक  
06.03.2019 और 25.03.2019 के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्णय  
(सा-सं- 43 / Defence-34 के लिए / 2016-SSW-1(Representation from Shri Sushil  
Kumar Saroj, Ex-Clerk of Danapur Cantonment Board to Danapur Cantonment Board dated  
06.03.2019 & 25.03.2019 and Decision of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC)  
vide F.No. 43/Defence-34/2016-SSW-1.)

दिनांक 06.03.2019 और 25.03.2019 को दानापुर कैंट बोर्ड के भूतपूर्व लिपिक श्री सुशील  
कुमार सरोज ने दानापुर कैंटोनमेंट बोर्ड के समक्ष अपनी अपील के संबंध में एक व्यक्तिगत  
सुनवाई के लिए अनुरोध किया है, जिसके संबंध में दिनांक 09.12.2016 और 13.01.2018 को  
जो पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था। ताजा दया अपील 06.03.2019 को पसंद की गई। श्री  
सुशील कुमार सरोज ने तत्कालीन सीईओ, दानापुर छावनी बोर्ड श्री विनीत कुमार द्वारा उनके  
विचारक जारी आरोप पत्र और बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने / खारिज करने का अनुरोध किया  
है। Vide letter dated 06.03.2019 & 25.03.2019 Shri Sushil Kumar Saroj, Ex-Clerk of Danapur  
Cantonment Board has requested for a personal hearing before Danapur Cantonment Board  
with regard to his appeal dated 09.12.2016 and 13.01.2018 which was already submitted and  
fresh mercy appeal preferred on 06.03.2019. Shri Sushil Kumar Saroj has requested to  
quash/dismiss the memorandum of charge sheet and dismissal order issued against him by the  
then CEO, Danapur Cantonment Board Shri Vineet Kumar.

श्री सुशील कुमार सरोज ने दानापुर छावनी बोर्ड की सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में राष्ट्रीय  
अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के समक्ष प्रतिनिधित्व किया है। एनसीएससी ने उनके पत्रों /

  
(Lakhimpuri Hrahsel, I.D.S.)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04.2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

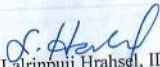
Dated

2019


आदेश संख्या F.No.S-43 / Defence-34/2016-SSW-1 को रद्द कर दिया है कि, "याचिकाकर्ता अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ उचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपनी याचिका दायर कर सकता है। दया अपील को जीओसी-इन-सी, मध्य कमान ने उनके आदेश दिनांक 28.09.2018 को खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने उचित प्राधिकारी के समक्ष अपनी अपील दायर नहीं की है। मामले में विभाग द्वारा एक जवाब भी प्रस्तुत किया जाता है। आयोग ने देखा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर की प्रति याचिकाकर्ता को भेजी जा सकती है। याचिकाकर्ता उचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपनी अपील दायर कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी बिना किसी पूर्वाग्रह के अपील का फैसला कर सकता है। 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की जा सकती है। Shri Sushil Kumar Saroj has represented before the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) regarding his dismissal from service of Danapur Cantonment Board. The NCSC vide their letters/order No. F.No.S-43/Defence-34/2016-SSW-1 has decided that, "The petitioner may file his before the appropriate appellate authority against the order of the disciplinary authority. The mercy appeal has been rejected by the GOC-in-C, Central Command vide his order dated 28.09.2018 as he has not filed his appeal before the appropriate authority. A reply is also submitted by the department in the matter. The Commission observed that the copy of the reply submitted by the department may be sent to the petitioner. The petitioner may file his appeal before the appropriate appellate authority. The appellate authority may decide the appeal without any prejudice. The action taken may be submitted within 30 days".

श्री सुशील कुमार सरोज, भूतपूर्व लिपिक, दानापुर छावनी बोर्ड के मामले की संक्षिप्त / कालानुक्रमिक घटनाएँ BRIEF/CHRONOLOGICAL EVENTS OF CASE OF SHRI SUSHIL KUMAR SAROJ, EX-CLERK, DANAPUR CANTONMENT BOARD

**14.05.2008:** तत्कालीन C.E.O., कैंट। बोर्ड ने सुशील क्रा. सरोज ने दो साल की प्रोबेशन के तहत लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में सर्टिफिकेट के साथ नौकरी के लिए आवेदन किया था, जिसमें दिखाया गया था कि उन्होंने वर्ष 1999 में मैट्रिकुलेशन पास किया था। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से 101 और कोड नंबर। **14.05.2008:** The then C.E.O., Cantt. Board appointed Sushil Kr. Saroj as Lower Division Clerk under two years' probation as he had

  
(Lalrinpuoi Hrahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04 2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

Dated

2019

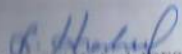


applied for the job with certificate showing that he had passed matriculation in the year 1999 bearing roll no.101& code no.13202 from Bihar School Examination Board.


16.05.2008 सुशील कऱ सरोज कैट से इस पद पर आसीन हुए। बोर्ड लेकिन पहले ही दिन से अपने कर्तव्य में भाग लेने में अनियमित था और इस तरह की उसकी सेवाएं कभी भी संतोषजनक नहीं हो सकती थीं। इसलिए, उनकी जांच की पूर्ण नहीं की गई थी 16.05.2008 Sushil Kr. Saroj joined the post with the Const. Board but remained irregular in attending his duty since the very day one and as such his services could never be satisfactory. Hence, his probation was never confirmed.

31.03.2009 केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने CBI / ACB / पटना RC023 / 2009 (Spl.9 / 2009) के तहत सुशील कुमार सरोज के खिलाफ उनकी नियुक्ति के लिए जारी और मनगढ़ंत मैट्रिकुलेशन- प्रमाण पत्र के आधार पर छावनी बोर्ड में नियुक्ति की। । लेकिन, उस व्यक्ति ने कैंटोनमेंट बोर्ड को उसके खिलाफ आपराधिक मामले की जानकारी कभी नहीं दी। 31.03.2009 Central Bureau of Investigation (C.B.I.) lodged CBI/ ACB/ Patna R.C.023/2009 (Spl.9/2009) against Sushil Kumar Saroj for procuring his appointment in the Cantonment Board on the basis of forged & fabricated matriculation- certificate. But, the person never informed the Cantonment Board about the criminal case against him.

28.05.2009 सी.बी.आई. भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध के लिए सुशील कुमार सरोज के खिलाफ आरोप सही और प्रस्तुत किया गया। हालांकि, सी.बी.आई ने सुशी के नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग रिपोर्ट के लिए कहा था। सरोज ने सी.ई.ओ. जिन्होंने तुरंत व्यक्तिगत संदेशवाहक के माध्यम से समान भेजा, लेकिन एफआईआर दर्ज करने या चांसेरीट दाखिल करने का तथ्य। तब बोर्ड को पता नहीं चल

  
(J. A. K. Yadav, I.D.S.)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment


Dated 26.04 2019


  
(Brig. A. K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

Dated 26/4/ 2019

सका। हालाँकि, इयूटी से अनुपस्थित रहने के कारण उसके मूल प्रमाण पत्र उससे मांगे गए थे। इसके परिणामस्वरूप, सुशील कुमार सरोज ने कहा कि उसकी पुष्टि नहीं हुई है। 29.05.2009 The C.B.I. found allegation true & submitted Charge-sheet against Sushil Kumar Saroj for offences under Sections 420, 467, 468, 471 of the Indian Penal Code. Even though, The C.B.I had asked for the appointment letter & Joining Report of Sushil Kr. Saroj from the C.E.O. who immediately sent the same through personal messenger but the fact of lodging of FIR or even filing of charge-sheet, could not be known to Board right then. However, the incumbent continued with his absence from duty as his original certificates were asked from him. Resultantly, the probation of Sushil Kr. Saroj continued artd he was not confirmed.

21.09.2010: उप सचिव, सतर्कता, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड, पटना ने तत्कालीन C.E.O., कैंट को सूचित किया। बोर्ड पर प्रश्न है कि वर्ष 1999 के रोल नंबर और कोड नंबर .13202 दूसरे छात्र के थे, सुशी के नहीं। कुमार सरोज इस प्रकार, सुशील द्वारा सुसज्जित मैट्रिकुलेशन-सर्टिफिकेट जाली और मनगढ़ंत प्रतीत हुआ। तब से, बोर्ड का कार्यालय सुशी से पूछ रहा है। अपने मूल प्रमाणपत्रों को बार-बार लिखने के साथ-साथ मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए लेकिन बोर्ड को एक जैसा दिखाने के बजाय, श्री सुशील कुमार सरोज ने बिली-डाल्लिंग को अपनाया और यहां तक कि पिता, पत्नी और अन्य लोगों की बीमारी के आधार पर अनुपस्थित रहने लगे। कई बार बिना किसी सूचना के भी। 21.09.2010 :The Deputy Secretary, Vigilance, Bihar School Examination Board, Patna intimated to the then C.E.O., Cantt. Board on query that Roll No.101 & Code No.13202 of the year 1999 belonged to another student and not Sushil Kumar Saroj. Thus, the matriculation-certificate furnished by Sushil appeared to be forged and fabricated one. Since then,

  
(Lalrinpui Hrahse, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment  
Dated 26.04 2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment  
Dated 26/4/ 2019


the office of the Board has been asking Sushil to furnish his original certificates time and again both orally as well as in writing but instead of showing the same to the Board, Shri Sushil Kumar Saroj adopted dilly-dallying and even started absents on the grounds of illness of father, wife and others and many times even without any information at all.


10.06.2011

बोर्ड ने एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया, जिसमें दैनिक DAINIK JAGRAN ने सुशील कुमार सरोज को तीन दिनों के भीतर अपनी इयूटी में शामिल होने के लिए कहा, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, क्योंकि वह व्यक्ति महीने में 1.11.2010 से 24.01.2011 तक इयूटी पर गैर-हाजिर रहा था। 1.2.2011 उस तिथि तक। एक तथ्यान्वेषी टीम गठित की गई जिसने सुशील कुमार सरोज को निलंबित करने की सिफारिश की। 10.06.2011 The Board published a public-notice in the daily DAINIK JAGRAN asking Sushil Kumar Saroj to join his duty within three days lest action be taken against him since the man had remained unauthorisedly absent from duty for months together from 8.11.2010 to 24.1.2011 till that date. A fact-finding team was constituted which recommended suspension of Sushil Kumar Saroj.

03.08.2011

बोर्ड ने सुशील को उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए निलंबित कर दिया और उनके मूल प्रशंसापत्र दिखाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका निलंबन बोर्ड के समय और फिर सहानुभूति पर बढ़ाए जाने पर रखा गया था, लेकिन अंतहीन रूप से नहीं बढ़ाया जा सका। 03.08.2011 The Board suspended Sushil for his unauthorized absence and for no response on showing his original testimonials. His suspension was kept on being,

  
(Lalrampati Hrahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment  
Dated 26.04.2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment  
Dated 26/4/2019



extended by the Board time and again on sympathy but couldn't be extended endlessly.

**25.08.2011** सुशील कुमार सरोज जेल गए और सी.बी.एल के संबंध में लगभग तीन महीने तक रहे। मैट्रिक-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अपने फर्जीवाड़े के लिए मामला दर्ज। लेकिन, शुरू में, उस व्यक्ति ने बोर्ड को जेल में उसके उत्पीड़न के बारे में सूचित नहीं करने के लिए चुना और बोर्ड को कार्यबल के नुकसान और प्रतिष्ठा के नुकसान दोनों के मामले में बहुत नुकसान उठाना पड़ा **25.08.2011** Sushil Kumar Saroj went in jail and remained therein for about three months in connection with C.B.L. Case lodged for his forgery of furnishing matriculation-certificate. But, initially, the man chose not to inform the Board regarding his incarceration in jail and the Board suffered a lot both in terms of loss of workforce and also loss of prestige.

**13.07.2015:** सुशील कुमार सरोज ने C.E.O को एक प्रतिनिधित्व दिया। अपने अनियमित पतों के नियमितीकरण के लिए और अपने निर्वाह-भत्ते को बढ़ाने के लिए, बेहतर प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ-साथ उससे बहुत पहले और बाद में भी बहुत कुछ दिया। अलग-अलग अदालतों के कई केस-कानूनों और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से मांगी गई सूचनाओं की एक अंतहीन संख्या के साथ कई अनुस्मारक देरी से भेजे गए हैं, कुछ कानूनी सलाह के तहत बोर्ड पर उन्हें निलंबन से राहत देने के लिए दबाव बनाना और साथ ही उसे वेतन वृद्धि की अनुमति देना, जिसमें से कोई भी उसके मामले के भयावह तथ्यों के साथ-साथ भूमि के बसे हुए कानून के मददेनजर नहीं किया जा सकता है।

**13.07.2015:** Sushil Kumar Saroj gave one representation to the


C.E.O. for regularization of his erratic leaves and also for increment of his subsistence-allowance with copies to the superior authorities in line a lot many more from him earlier and even later. Several reminders have been sent by the man of late, with several case-laws of different courts and an endless numbers of information sought under the Right to information Act apparently under some legal-advice building a pressure on the Board to relieve him from suspension and also to allow increments to him neither of which could be done in the glaring facts of his case as also in view of the settled law of the land.

26.12.2015


सी.ई.ओ. सुशील कुमार को नोटिस जारी किया। सरोज ने उसे अपनी अनधिकृत अनुपस्थिति के बारे में दिखाने का कारण पूछा और आगे उसे अपना मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र मूल या प्रमाणित प्रति में प्रस्तुत करने के लिए कहा, ऐसा न हो कि उसकी सेवा को अपनी प्रारंभिक नियुक्ति को अवैध करार दिया जाए। लेकिन, उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। **26.12.2015** : The C.E.O. issued a notice to Sushil Kr. Saroj asking him to show-cause about his unauthorised absence and further asking him to submit his matriculation certificate either in original or a certified copy hereof lest his service is terminated holding his initial itself appointment as illegal. But, the man did not respond.

27.01.2016

फिर, कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद सुशील कुमार सरोज को फिर से एक चार्ज-लापन जारी किया गया था। दिनांक 27.01.2016 द्वारा अपने दम पर कदम उठाने के लिए। हालांकि, परिवीक्षाधीन कर्मचारी ने न तो अपना मैट्रिक-प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और न ही अपनी संतुष्टि के लिए

  
(Lalrampul Hrahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04.2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

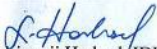
Dated 26/4/2019




अनधिकृत अनुपस्थिति को समझाया। 29.02.2016 Then, again, a charge-memo was issued to Sushil Kumar Saroj after the Cantonment Board authorized the C.E.O. to take steps on his own by resolution dated 27.01.2016. However, the employee under probation neither submitted his matriculation-certificate nor explained his unauthorized absence to his satisfaction.

24.05.2016:

बिना किसी विकल्प के वामपंथियों ने सी.ई.ओ. विधिवत रूप से एमडी। फिरोज को जांच अधिकारी के रूप में, श्रीराम कुमार सिंह को, उपस्थित अधिकारी के रूप में अधिवक्ता और श्री तिवारी ने अपराधी के पूछने पर रक्षा-सहायक नियुक्त किया। जांच अधिकारी के समक्ष अपराधी ने अपना लिखित बयान दर्ज नहीं कराया; माननीय भारत के राष्ट्रपति सहित शीर्ष-अधिकांश लोगों के समक्ष निरर्थक याचिकाएं भेजना शुरू कर दिया ताकि कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो और यहां तक कि उपस्थित अधिकारी राम कुमार सिंह को भी धमकी दी, जिसके परिणामस्वरूप खुद को कार्यवाही से हटा लिया। जाँच-अधिकारी द्वारा सूचना पर, सी.ई.ओ. अमरेंद्र एन एथलीट वर्मा, बोर्ड के एडवोकेट को नए P.O के रूप में नियुक्त किया गया। परिश्रम के तहत। आगे बढ़ने और विलंबित गैर-सहयोग और अनियंत्रित रवैये के बीच आगे बढ़े। 24.05.2016 : Left with no option, a proceeding was initiated by the C.E.O. duly appointing Md. Firoz as the enquiry-officer, Mr. Ram Kumar Singh, Advocate as the presenting officer and Mr. Tiwaryas the defence-assistant on the askance of the delinquent. The delinquent chose not to file his written statement before the enquiry-officer; started sending meaningless petitions before the top-most people including the Hon'ble President of India simply to obstruct the proceeding and even threatened the

  
(Lalrinpuij Hrahse, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment


Dated 26.04 2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment  
Dated 26/4/2019


presenting officer Ram umar Singh who consequently withdrew himself from the proceeding. On information by the Enquiry-officer, the C.E.O. appointed Amarendra Nath Verma, Advocate of the Board as new P.O. under the exigencies. Proceeding progressed & concluded amid the delinquent's non-co-operation and unruly attitude.

11.09.2016:

जांच-अधिकारी ने मैट्रिकुलेशन-सर्टिफिकेट में तीनों गणनाओं के निर्माण पर परिसीमन के अपराध का पता लगाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो मूल / प्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ-साथ अनधिकृत अनुपस्थिति द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति का उत्पादन नहीं कर रहा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई नहीं आया और उसने यह दर्शाया कि नियुक्ति प्राप्त करने के लिए परिसीमन द्वारा प्रस्तुत 1999 असर रोल नंबर -101 और कोड नं। 1,3202 के मैट्रिकुलेशन-सर्टिफिकेट को सारणीयन-रजिस्टर के लिए वास्तविक नहीं था। उसी को दूसरे व्यक्ति से संबंधित दिखाया गया था। हालांकि फाग के अंत में, उनकी नियुक्ति के बाद पहली बार अपराधी ने कहा कि उसने 1991 के प्रमाण पत्र पर अपनी नियुक्ति प्राप्त की है और उस प्रमाण पत्र को जमा करने के लिए काम किया है, लेकिन उसने इसे जमा करने का विकल्प नहीं चुना और न ही इसके बारे में कोई प्रमाण दिया। इसके अलावा, यदि वह वर्ष 1991 में मैट्रिक पास कर लेता, तो वह 32 वर्ष का हो जाता। और नियुक्ति के लिए अयोग्य। 11.09.2016 : The Enquiry-officer submitted his report finding guilt of the delinquent on all the three counts fabrication in matriculation-certificate, not producing the original/ authenticated certificate as well as unauthorized absence by the delinquent. None other than the authorized person from the Bihar School Examination Board came and deposed that the matriculation-certificate of

  
(Lalrinpuii Hrahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04.2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

Dated 26/4/2019

1999 bearing roll no.101 & code no.13202 submitted by the delinquent for getting appointment was not genuine for in the tabulation-register the same was shown belonging to another person. Though at the fag end, the delinquent for the first time since his appointment pleaded that he had got his appointment on 1991 certificate and undertook to submit that certificate but he chose not to submit that nor any proof regarding it. Also, if he would have passed matriculation in the year 1991, he would have become 32 yrs. and so unfit for appointment.

05.11.2016:


कैंटोनमेंट फंड सर्वेंट्स रूल्स 1937 के नियम १२ (ए) (४) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्राधिकारी के रूप में सीईओ को सेवा से बर्खास्तगी का बड़ा जुर्माना लगाया गया, जो बोर्ड के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य होगा। आरोपित कर्मचारी को CFSR, 1937 के नियम 11 (2) (VIII) के तहत बर्खास्तगी या किसी अन्य बोर्ड के समय नियोजित किया गया था। 05.11.2016:

The C.E.O., as appointing authority in exercise of powers conferred under rule 12(A)(4) of Cantonment Fund Servants Rules 1937 imposed major penalty of dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Board under whom the charged employee was employed at the time of dismissal or any other Board under rule 11 (2)(VIII) of CFSR, 1937.

तत्पश्चात श्री सुशील कुमार सरोज ने C.E.O, दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा जारी सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ GOC-in-C, मध्य कमान, लखनऊ के समक्ष दिनांक 09.12.2016 को दया अपील प्रस्तुत की। तत्पश्चात जीओसी-इन-सी द्वारा दोनों पक्षों यानी श्री सुशील कुमार सरोज / उनके प्रतिनिधि और छावनी बोर्ड, दानापुर / प्रतिनिधि-विधिक परामर्शदाता

  
(Lahripui Hahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04 2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment


Dated 26/4/ 2019




के समक्ष कई दलीलें पेश की गईं और दलीलें / प्रतिवाद प्रस्तुत किए गए। जीओसी-इन-सी, मध्य कमान, लखनऊ ने आदेश दिनांक 28.09.2018 को आदेश दिया कि दया अपील दिनांक 09.12.2016 को समय से पहले और कानूनी रूप से ठीकाऊ नहीं है। अपीलीय प्राधिकारी की खोज और निर्णय इस प्रकार है: Thereafter Shri Sushil Kumar Saroj submitted a mercy appeal dated 09.12.2016 before the GOC-in-C, Central Command, Lucknow against the order of the dismissal from service issued by the C.E.O, Danapur Cantonment Board. Thereafter several hearings were conducted by the GOC-in-C with both parties i.e. Shri Sushil Kumar Saroj/His representative and Cantonment Board, Danapur/representative-Legal counsel present and submitting arguments/counter-arguments. The GOC-in-C, Central Command, Lucknow vide order dated 28.09.2018 dismissed the mercy appeal dated 09.12.2016 as being premature and legally not sustainable. The finding and decision of the appellate authority is as follows:

"जबकि, सीएफएसआर, 1937 के नियम 14 (1) के तहत मुझ में निहित शक्तियों के अनुसार, मैंने इस मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड / तथ्यों के आधार पर संपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है और मेरे निष्कर्ष और निर्णय सफल पैराग्राफ में निहित हैं।" Whereas, in accordance with the powers vested in me under Rule 14(1) of CFSR, 1937, I have deliberated upon the issues in entirety based on relevant records/facts of the case and my findings and decision thereon are contained in succeeding paragraphs.

यह अधोहस्ताक्षरी है जिसमें वैधानिक शक्तियां निर्णय लेने की शक्ति देती हैं, जो कि उचित आशा और वैध अपेक्षाओं के साथ होती है कि इस तरह के रैंक और कद पर, एक समय दृष्टिकोण लिया जाएगा और एक विवेकपूर्ण निर्णय आया। अब, इसलिए, मैंने जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों, अपीलीय और उत्तरदाता और उसके मूल्यांकन दोनों के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री, जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूत और मामले से

  
(Lalrinpuii Hrahnel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

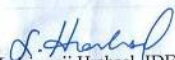
Dated 26.04.2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment  
Dated 26/4/2019


संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया है। इस तथ्य से इनकार नहीं है कि अपीलकर्ता की सेवाओं को छ्वानी बोर्ड, दानापुर द्वारा तीन बार समाप्त कर दिया गया था। It is the undersigned in whom the statute vests powers to decide, albeit with the reasonable hope and legitimate expectations that at such rank and stature, a holistic view shall be taken and a judicious decision arrived at. Now, therefore, I have taken a considered view of the facts presented in the Enquiry Report, contentions presented by both the Appellate and the Respondent and its evaluation thereof, evidence adduced during Enquiry and available on record and all relevant factors pertaining to the case. There is no denial to the fact that the services of the Appellant were terminated thrice by the Cantonment Board, Danapur.

हालाँकि, तात्कालिक अपील के दस्तावेजों के अवलोकन के दौरान, यह सामने आई है कि अपीलार्थी को आदेश द्वारा दिनांक ०५.११.२०१६ में नाराजगी जताई गई है, जिसे अनुशासन प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है, जिसके तहत सेवा से "बर्खास्तगी" के प्रमुख दंड सीएफएसआर, १९३७ के नियम ११ (२) (viii) को नियम १२ के तहत शक्तियों के अभ्यास में प्रयुक्त किया गया था (ए (४) ने एक अपील को प्राथमिकता दी है। नियम (ए) (४) जो निम्नानुसार पढ़ता है: However, during the course of perusal of the documents of the instant Appeal, it has come to light that the Appellant having been aggrieved by - the order dated 05.11.2016 passed by the Disciplinary Authority, whereby the Major Penalty of "Dismissal from Service" under Rule 11(2)(viii) of CFSR, 1937 was awarded in exercise of powers under Rule 12(A)(4) has preferred an Appeal Rule(A)(4) which reads as under:-

"यदि अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पास सभी या किसी भी लेख के आरोप और पूछताछ के दौरान जोड़े गए साक्ष्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों के संबंध में राय है कि क्लॉस (iv) (viii) में निर्दिष्ट दंड में से कोई भी

  
(Lalrnpuii Hrahse, IDDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04 2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

Dated 26/4/ 2019

नियम 11 के खंड (2) को नौकर पर लगाया जाना चाहिए, यह इस तरह का निर्णय लगाने का आदेश देगा और नौकर को लगाए गए दंड पर प्रतिनिधित्व करने का कोई भी अवसर देने के लिए आवश्यक नहीं होना चाहिए। "If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the Articles of Charges and on the basis of the evidence adduced during the Enquiry is of the opinion that any of the penalties specified in Chapter (II) in (a) of Clause (2) of Rule 11 should be imposed on the servant, it shall make an order imposing such penalty and it should not be necessary to give the servant any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed."

सीएफएसआर, 1937 के नियम 12 (ए) (4) का कहीं भी यह अर्थ नहीं है कि अपीलकर्ता को जीओसी-इन-सी, मध्य कमान, लखनऊ में एक प्रत्यक्ष अपील को प्राथमिकता देने का अधिकार है, इस संबंध में भी अपीलकर्ता के पास वैकल्पिक विकल्प थे। सीएफएसआर, 1937 के नियम 13 (1) के प्रावधानों के संदर्भ में उपाय, जिसमें अपीलकर्ता छावनी बोर्ड, दानापुर को दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील को प्राथमिकता दे सकता था। अपीलकर्ता को उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया गया है। और इसलिए, नियम की स्थिति को देखते हुए, अपीलकर्ता ने जीओसी-इन-सी, सेंट्रल कमान में प्राथमिकता दी और यह समय से पहले तकनीकी रूप से बनाए रखते योग्य नहीं है। इसके अलावा, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर सामग्रीय आधार पर दिया गया है, जिसमें उसे अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र और जिम्पश अवसर की अनुमति दी गई है। The Rule 12(A)(4) of the CFSR, 1937, nowhere implies that the Appellant has the right to prefer a direct Appeal to the GOC-in-C, Central Command, Lucknow. Also in this regard, the Appellant had alternate remedy in terms of provisions of Rule 13(1) of the CFSR, 1937 wherein the Appellant could have preferred an Appeal against the impugned order to the Cantonment Board, Danapur. The alternate remedy available to the Appellant has not

(1) Arjun Kumar Hrahsel, (DES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26/04/2019

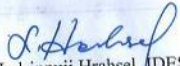
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment


Dated 26/4/2019



been availed by him. And therefore, in view of the Rule position, the Appeal preferred by the Appellant to the GOC-in-C, Central Command is premature and thus technically not maintainable. Further, the opportunity of hearing afforded to the Appellant has been accorded on humanitarian grounds, wherein he has been allowed free and fair opportunity to present his case.

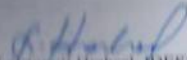
मामले के दस्तावेजों की गड़बड़ी इस तथ्य को सामने लाती है कि आरसी -9 (एस) / 2009 की एक पहली सूचना रिपोर्ट सीबीआई और पोस्ट जांच द्वारा दर्ज की गई है, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमे का सामना कर रहा है। न्यायालय ने श्री प्रवीण कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई- IV, पटना को सीखा। उक्त मामला अभी भी इससे निस्तारण के लिए लंबित है। यह कानून अच्छी तरह से तय है कि आपराधिक प्रसंस्करण और विभागीय कार्यवाही दो अलग-अलग कार्यवाही हैं और दोनों की उत्पत्ति और परिणाम अलग-अलग हैं। यह एक व्यक्ति की समाप्ति पूरी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के प्रावधानों या मामले में लागू वैधानिक नियमों में किसी भी अनुरूप प्रावधानों के मददेनजर आपराधिक न्यायालय द्वारा दी गई सजा पर आधारित है, तब बरी होना या सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा डिस्चार्ज केवल और केवल कर्मचारी को बहाल कर सकता है, जबकि अगर एक जांच को आपराधिक कार्यवाही से स्वतंत्र रूप से आयोजित किया गया है, तो भी आपराधिक अदालत में बरी या डिस्चार्ज से कोई मदद नहीं मिलेगी। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को एक उचित विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वैधानिक सीएफएस नियम, 1937 के तहत शुरू किया गया है। इसलिए, यहां तक कि अपराध न्यायालय से अपीलकर्ता को बरी होने या छुट्टी देने से अपीलकर्ता को विभागीय कार्यवाही में मदद नहीं मिल सकती है। उसकी बर्खास्तगी में परिणत। उपर्युक्त स्थिति को देखते

  
(Lalrinpui Hrahse, JDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment  
Dated 26.04 2019


  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment  
Dated 26/4/ 2019

हुए, अपील के निपटान के तरीके या तो चल रहे आपराधिक जांच पर असर डाल सकते हैं और चल रहे आपराधिक मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतीक का कारण बन सकते हैं, जो कि उनके खिलाफ प्रवीण कुमार सिंह के न्यायालय में लंबित है। विशेष न्यायाधीश, सीबीआई- IV, पटना। The disposal of these documents brings forth the fact that a First Information Report bearing No. 9 (5)/2009 has been lodged by the CBI and post arrestment, the Charge Sheet has been submitted against the Appellant herein, who is facing trial in the Court of learned Shri Praveen Kumar Singh, Special Judge, CBI IV, Patna. The said case is still pending for its disposal. That the law is well settled that the Criminal Processing and Departmental Disciplinary Proceedings are two separate proceedings and both of them have separate rights and consequences. If the termination of an individual is solely based on conviction by the Criminal Court in view of the provisions of Article 311(2)(b) of the constitution of India or any analogous provisions in the statutory rules applicable in the case, then the acquittal or discharge by a Competent Criminal Court may only and only reinstate the employee, whereas if an enquiry has been held independently of the Criminal proceeding, even the acquittal or discharge in the Criminal Court will be of no help. In the present case, the Appellant has been Dismissed from service in a proper departmental disciplinary proceeding, initiated under statutory FFS Rules, 1957. Therefore, even the acquittal or discharge of the Appellant from the Criminal Court cannot help the Appellant in the departmental proceeding which has culminated into his dismissal. In View of the above stated position, disposal of the Appeal either ways could and would have a bearing on the ongoing Criminal Investigation and may cause prejudice to the Appellant in the ongoing Criminal Proceeding pending against him in the Court of learned Shri Praveen Kumar Singh, Special Judge, CBI IV, Patna.

सम्बन्धित मामले के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और उसे ध्यान में रखते हुए, मैं अपीलीय प्राधिकारी के रूप में, उचित आवेदन के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उपलब्ध वैकल्पिक उपाय के कारण और अपीलकर्ता

  
(H. H. H. H.)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04.2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

Dated 26/4/2019


के खिलाफ लंबित सीबीआई कार्यवाही के कारण, यह अपीलकर्ता के सर्वोत्तम हित में है कि उसके द्वारा पसंद की गई अपील इस चरण में तय नहीं की जा सकती है। In view of the foregoing and taking a humanitarian approach towards the instant case, I as the Appellate Authority, after due application of mind, have come to the conclusion that owing the clause of Alternate remedy available and the pending CBI proceeding against the Appellant, it is in the best interest of the Appellant that the Appeal preferred by him may not be decided at this stage.

अब, इसलिए, छावनी निधि के नियम 1937 के नियम १४ (१) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, मैं अपीलीय प्राधिकारी के रूप में, समग्रता में मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यह विचार है कि दया अपील दिनांकित है 09.12.2016 को समय से पहले और कानूनी रूप में टिकाऊ नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया। Now, therefore, in exercise of powers conferred under Rule 14(1) of the Cantonment Fund Servants Rule 1937, I as the Appellate Authority, having taken into account all aspects of the case in totality, is of the view that the mercy Appeal dated 09.12.2016 be dismissed as being Premature and legally not sustainable".

**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के समक्ष अपील Appeal before National Commission for Scheduled Castes (NCSC)**

याचिकाकर्ता श्री सुशील कुमार सरोज ने भी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के सामने अपील की कि कैंटोनमेंट बोर्ड, दानापुर की सेवा में उनकी बर्खास्तगी के बारे में 18.09.2018 और 26.11.2018 में 15.01.2019 को प्रो। (डॉ।) राम शंकर द्वारा सुनवाई की गई थी। कठोर माननीय अध्यक्ष एनसीएससी। एनसीएससी के पत्र की फाइल संख्या एन 43 / डीईईएफएनईएसई -34 / 2016-एसएसडब्ल्यू, मैंने दिनांक 19.02.2019 को 15.01.2019 को आयोजित सुनवाई के मिनटों को

  
(Lalrinpui Hrahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment  
Dated 26.04 2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment  
Dated 26/4/ 2019



समाप्त है, जिसमें, विभाग का प्रतिनिधित्व डीजीडीई, दिल्ली टीटी द्वारा किया गया था। टीटा बाजवा और श्रीमती। सोनम यांगडोल, एडेल। महासचिव, इस संघदा, अधिकारकर्ता श्री सुशील कुमार सरोज भी उपस्थित थे। सुनवाई का समय इस प्रकार है: The Petitioner Shri Sushil Kumar Saroj जोत उपस्थित है। before the National Commission for Scheduled Castes (NCS) for dismissal from service of Cantonment Board, Danapur (NCS) was held on 18.09.2018 and 26.11.2018 & 15.01.2019 by Pres. (M) Ram Shankar Katheria Hon'ble Chairman NCS. The case was filed under File No. 5-43/DEFENCE-34/2016-SSW, 1 dated 15.01.2019. The minutes of the hearing held on 15.01.2019 (NCS), the Department was represented by DGDE, Delhi Smt. Deepa Katheria and Smt. Sonam Yangdol, Addl. Director General, Defence Estates, The Petitioner Shri Sushil Kumar Saroj was also present. The minutes of the hearing is as follows:

“समाप्त इसका समय, अधिकारकर्ता ने आयोग को अवगत कराया कि विभाग द्वारा उसे जानबूझकर परेशान किया गया है। उन्हें 08.11.2016 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि दो जांच, यानी विभागीय जांच, सीबीआई जांच एक साथ नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि यदि भारतीय न्यायालय के समक्ष मामला लंबित है, तो विभागीय कार्यवाही एक साथ नहीं की जा सकती। “The case was taken up, The petitioner apprised the Commission that he has been deliberately harassed by the Department. He was dismissed from job on 08.11.2016. He alleged that two enquiries, i.e. Departmental enquiry, CBI enquiry can not be conducted simultaneously. He further added that if the case is pending before the Hon'ble Court, then departmental proceedings can not be done simultaneously.

सीजी, डीफेंस एस्टेट्स ने आयोग को सूचित किया कि दिनांक 21.07.2016 को सीओपीटी आदेश संख्या 11012/6/2007-एस्टट 9 ए-तृतीय) के अनुसार,

(Signature)  
(L. Anand Prasad, DGS)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04, 2019

(Signature)  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

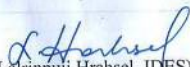
Dated 26/4 2019

विभाग की कार्यवाही एक साथ की जा सकती है जहां एक जांच एजेंसी एक जांच कर रही है और जिसके खिलाफ एक आरोप है कोर्ट में चादर दाखिल की गई है। The DG, Defence Estates informed the Commission that as per DOPT Order No. 11012/6/2007-Estt9A-III) dated 21.07.2016, the department proceedings may be done simultaneous where an investigating Agency is conducting an investigation or against whom a charge sheet has been filed in the court.


याचिकाकर्ता अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ उपयुक्त अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपनी अपील दायर कर सकता है। इस अपील को GoC-in-C, सेंट्रल कमांड ने 28.09.2018 के अपने आदेश को रद्द कर दिया है क्योंकि उन्होंने उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष अपनी अपील दायर नहीं की है। विभाग द्वारा मामले में एक जवाब भी प्रस्तुत किया जाता है। The Petitioner may file his appeal before the Appropriate Appellate Authority against the order of disciplinary Authority. The matter appeal has been rejected by GoC-in-C, Central Command vide his order dated 28.09.2018 as he has not filed his appeal before the Appropriate Authority. A reply is also submitted by the Department in the matter.

आयोग ने देखा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर की प्रति याचिकाकर्ता को भेजी जा सकती है। The Commission observed that the copy of the reply submitted by Department may be sent to the petitioner.

याचिकाकर्ता उचित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपनी अपील दायर कर सकता है। अपील प्राधिकारी बिना किसी पूर्वाग्रह के अपील का फैसला कर सकता है। The petitioner may file his appeal before the appropriate Appellate Authority. The Appealed authority may decide the appeal without any prejudice.

  
(Lalrinpui Hrahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04 2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

Dated 26/4/ 2019

एक्साइन टेकन रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है। The Appeal Taken Report may be submitted within 30 days".

सुश्री के शिकायती की सेवा छावनी बोर्ड दानापुर कार्यालय द्वारा 28.03.2019 को श्री सुशील कुमार सरोज को दी गई, उसके बाद दिनांक 28.03.2019 को श्री सुशील कुमार सरोज से 28.03.2019 को छावनी बोर्ड, दानापुर के कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया। अपील दिनांक 25.03.2019 को प्राप्त होते पर, मामले को एस.डी. संजय, द एडल सॉलिसिटर जनरल मामले पर कागज़ी राय के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, पटना। प्रसंग की गई कागज़ी राय इस प्रकार है: The minutes of the meeting held (convened by the Cantonment Board Danapur Office on 28.03.2019) in which Shri Sushil Kumar Saroj, thereafter an appeal dated 25.03.2019 was received from Shri Sushil Kumar Saroj on 28.03.2019 by the office of Cantonment Board, Danapur. On receipt of the appeal 25.03.2019, the meeting was referred to Shri S.D. Sanjay, the Addl. Solicitor General of India, India High Court, Patna, for legal opinion on the matter. The legal opinion received is as follows:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी बोर्ड, दानापुर ने श्री सुशील कुमार सरोज की अपील को अपील प्राधिकारी (छावनी बोर्ड) को अयोधित करने के मुद्दे पर श्री कागज़ी राय मांगी है, जिसके परिणामस्वरूप हेड क्वार्टर के पत्र पर विचार किया गया है। उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी द्वारा श्री सुशीला कुमार सरोज के मामले पर विचार के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली। उन्होंने अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा सजा के मूल आदेश वाली दो पाइली को भी अयोधित कर दिया है, जो छावनी बोर्ड, दानापुर के तकनीकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के साथ-साथ कमांड चीफ ऑफिसर कमांडिंग द्वारा दया अपील आदेश भी हैं। उसने छावनी निधि सेवा विभागकी, 1937 की एक प्रति भी भेज दी है, जिसमें छावनी बोर्ड के

(Signature)  
(Member Secretary)  
Danapur Cantonment

Dated 26/04/2019

(Signature)  
(Brig. A.K. Yadav)

President

Danapur Cantonment

Dated 26/4/2019




कर्मचारियों की सेवा शर्त को शामिल किया गया है, जिसे छावनी अधिनियम, 1937 की धारा 280 के तहत भारत सरकार द्वारा शक्ति प्रयोग में फंसाया गया है। "The Chief Executive Officer, Cantonment Board Danapur has sought my legal Opinion on the issue of forwarding the Appeal of Shri Sushil Kumar Saroj to the Appellate Authority (Cantonment Board) for consideration in view of the letter of Head Quarter consequent upon the order of National Commission for Scheduled Castes, New Delhi for consideration of the case of Shri Sushila Kumar Saroj by the appropriate Appellate Authority. She has also forwarded two Files containing the original order of punishment by the Disciplinary Authority, being the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, Danapur and also the mercy Appeal order by the Officer Commanding in Chief of the Command. She has also forwarded a copy of the Cantonment Funds Servants Rules 1937 governing the Service Condition of the Employees of the Cantonment Board which has been framed in exercise of power by the Government of India under Section 280 of the Cantonment Act, 1937.

तथ्यों को ट्रेस करने से पहले, यह भारत में कैंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले नियमों के प्रावधानों से निपटने के लिए सबसे प्राथमिक उचित होगा और उक्त नियम की धारा 1 (2) में निर्धारित किया गया है जो सभी नियोजित व्यक्तियों द्वारा लागू होगा। भारत में कैंटोनमेंट बोर्ड धारा 2 (एफ) ने (सेवक 'शब्द को परिभाषित किया है कि बोर्ड के तहत किसी समय की नियुक्ति रखने वाला व्यक्ति चाहे वह सार्वजनिक राजस्व से पेंशन प्राप्त करे या नहीं। Before traversing to the facts it would be more appropriate to deal with the provisions of the rules governing the employees of the Cantonment Board in India and Section 1(2) of the said Rule has laid down that it shall apply to all persons employed by the Cantonment Board in India. Section 2(f) has defined the term 'Servant' to mean a person holding a substantive whole time appointment under the Board whether any receipt from pension from public revenues or not.


नियम 11 ने विभिन्न श्रेणियों के मामूली और प्रमुख दंड के बारे में बताया  
जाता है। नियम 11 (ए) एक अधिकार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के  
बारे में बात करता है जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुरू किया जा सकता  
है। Rule 11 has laid down about minor and major penalty of different  
categories. Rule 11(a) talks about disciplinary proceeding against a servant  
which is initiated by the appointing authority.

नियम 12 अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के  
लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है।  
Rule 12 has laid down in detail about the procedures to be followed for  
the disciplinary proceedings by the Disciplinary Authority.

नियम 13 ने यह निर्धारित किया है कि नियम 11 में निर्दिष्ट किसी भी  
सेवक को अधिशासी अधिकारी द्वारा लगाया गया है, दंड के आधार दिखाते  
हुए दस्तावेज के वितरण के 30 दिनों के भीतर बोर्ड को अपील करने का  
अधिकार होगा या प्राप्त होने पर। बोर्ड का निर्णय। इस प्रकार, नियम 13  
(1) के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आदेश अध्यादेश फैक्टरी के  
खिलाफ पहला अपील फोरम किसी कर्मचारी को नियम 11 के तहत कोई  
अपील बोर्ड के समक्ष रखने के लिए प्रदान की गई है और कोई नहीं। Rule  
13 has laid down that any servant whom any of the penalty specified in  
Rule 11 has been imposed by the Executive Officer shall be entitled to  
Appeal to the Board within 30 days of delivery of document showing the  
grounds of penalty was imposed or upon receiving of the decision of the  
Board. Thus, it becomes clear from the reading of Rule 13(1) that the First  
Appeal Forum against the order Ordinance Factory any Appeal under Rule  
11 to an employee has been provided to be before the Board and none  
else.

  
(Lalitpur Hrahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

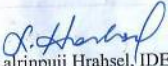
Dated 26.04, 2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment


Dated 26/4/ 2019

धारा 13 के उप-नियम (2) ने कमांड चीफ में कमांडिंग ऑफिसर के समक्ष द्वितीय अपील के लिए रखी है। यहां, यह उल्लेख करने के लिए जगह बाहर नहीं हो सकता है कि नियम 14 यह प्रदान करता है कि जब नियम 11 के तहत जुर्माना बोर्ड द्वारा लगाया जाता है, तो कमांड के चीफ ऑफिसर कमांडिंग से पहले पहली अपील को प्राथमिकता दी जा सकती है। तत्पश्चात, नियम 15 के संदर्भ में, व्यथित व्यक्ति को केंद्र सरकार के समक्ष संशोधन के माध्यम से एक और उपाय मिल गया है। इस प्रकार, यह है कि नियमों के तहत अपील की पदानुक्रम कैसे प्रदान की गई है। Rule (2) of Section 13 has laid down for Second Appeal before the Officer Commanding in Chief of the Command. Here, it may not be out of place to mention that Rule 14 provides that when the penalty under Rule 11 is imposed by the Board then the first Appeal could be preferred before the Officer Commanding in Chief of the Command. Thereafter, in terms of Rule 15 the person aggrieved has got another remedy by way of Revision before the Central Government. Thus, this is how the hierarchy of Appeals have been provided in detail under rules.

वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, बायार्ड के कर्मचारी, अर्थात्, सुशील कुमार सरोज, जो कि रिकॉर्ड के अनुसार, उनके अपॉइंटमेंट लेटर डीपी के लोअर डिवीजन असिस्टेंट के पद पर नियुक्त थे। 14.05.2008 को नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात्, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी बोर्ड, दानापुर। यह रिकॉर्ड से आगे प्रतीत होता है कि चूक के कुछ अधिनियम के संबंध में आयोग ने कहा कि कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही में आगे बढ़ाया गया था और उसके बाद जांच रिपोर्ट नियुक्त करने वाले प्राधिकारी, अर्थात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही भी हुई थी, बोर्ड के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता के साथ सेवा से बर्खास्तगी के प्रमुख दंड की सजा के साथ उसे दोषी ठहराया। नियम 11 (2) (viii)

  
(Lalrinpuui Hrahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04.2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

Dated 26/4/2019

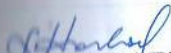


और नियम 11 (2) (viii) के तहत शक्ति के अभ्यास में सजा दी गई है।


11. Again, looking on the facts of the present case the employee of the Board, namely, Shri. Sushil Kumar Seroj, who as per the record, was appointed on the post of Lower Division Assistant vide his Appointment Letter No. 1408/2008 by the Appointing Authority, namely, the Chief Executive Officer, Cantonment Board, Danapur. It further appears from the record that with respect to certain act of omission or commission the said employee was proceeded in a disciplinary proceeding and thereafter upon submission of Enquiry Report the Appointing Authority, namely, the Chief Executive Officer, who also happened to the disciplinary proceeding, inflicted him with the punishment of major penalty of dismissal from service with disqualification for future employment under the Board. The penalty has been inflicted in terms of Rule 11(2)(viii) and in exercise of power under Rule 11(2)(viii).

इस प्रकार, मुख्य दंड अधिकारी, छावनी बोर्ड, दानापुर द्वारा पारित किए गए प्रमुख दंड के इस आदेश के खिलाफ, कर्मचारी का उपाय था कि बोर्ड के समक्ष नियम 13 के तहत एक अपील को प्राथमिकता दी जाए, न कि मुख्य अधिकारी के समक्ष। चीफ कमांडिंग इन चीफ सेकेंड अपील की स्टेज पर अपीलीय अधिकारी के रूप में हुआ और पहली अपील नहीं। यहां, यह उल्लेख करने के लिए जगह से बाहर नहीं हो सकता है कि मुख्य कमांडिंग ऑफिसर पहली अपील तभी सुन सकता है जब सजा बोर्ड द्वारा हो सकती हो और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नहीं। हालांकि, वर्तमान मामले में, यह प्रतीत होता है कि कर्मचारी, श्री सुशील कुमार सरोज ने बोर्ड के समक्ष अपनी अपील दायर करने के बजाय गलत फोरम का चयन किया है और कमांड चीफ में कमांडिंग ऑफिसर के समक्ष अपनी दया अपील दायर की है।

Thus, against this order of imposition of major penalty which was passed by the Chief Executive Officer, Cantonment Board, Danapur the remedy of the employee was to prefer an Appeal under Rule 13 before the Board itself and not before the Officer Commanding in Chief because the Officer

  
(Lalrampuli Hrahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04 2019

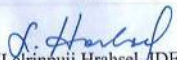
  
(Brig. A.K. Yadav)  
President

Danapur Cantonment


Dated 26/4/ 2019

Commanding in Chief happened to be the Appellate Authority at the stage of Second Appeal and not first Appeal. Here, it may not be out of place to mention that Officer Commanding in Chief could hear the First Appeal only when the punishment could have been by the Board and not by the Chief Executive Officer. However, in the present case, it appears that the employee, Shri Sushil Kumar Saroj, instead of filing his Appeal before the Board have chosen wrong Forum and filed its mercy Appeal before the Officer Commanding in Chief of the Command.

15.01.2019 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के सार्वजनिक आयोजित सुनवाई के कार्यक्रम के अवलोकन पर, NCSC के सदस्य डॉ. योगेंद्र पासवान की मौजूदगी में, जहाँ श्रीमती। दीपा बाजवा, महानिदेशक रक्षा संपदा, रक्षा मंत्रालय, श्रीमती। सोनम यंगडोल, अतिरिक्त महानिदेशक रक्षा संपदा, रक्षा मंत्रालय जिसमें यह सदस्य, NCSC द्वारा आयोजित किया गया था कि श्री सुशील कुमार सरोज, जो आयोग के सार्वजनिक याचिकाकर्ता थे, अनुशासन के आदेश के खिलाफ उपयुक्त अपील प्राधिकरण के समक्ष अपना अपील दायर कर सकते हैं। प्राधिकरण प्रतीत होता है कि आदेश को डी.जी. वीडियो पत्र डी.टी. 19.02.2017 को सुशील कुमार सरोज को जानकारी के साथ अपने निदेशक के माध्यम से फाइल में उपलब्ध प्रतिलिपि। On perusal of the Minutes of the hearing held before the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) on 15.01.2019 in presence of Dr. Yogendra Paswan, Member, NCSC, where Smt. Deepa Bajwa, The Director General, Defence Estates, Ministry of Defence, Smt. Sonam Yangdol, Additional Director General, Defence Estates, Ministry of Defence wherein it was held by the Member, NCSC that the Said Shri Sushil Kumar Saroj who was the Petitioner before the Commission may file his Appeal before the appropriate Appellate Authority against the order of Disciplinary Authority. The said order appears to have been communicated to the D.G. vide letter dt. 19.02.2017 through the Director with information to Shri Sushil Kumar Saroj. Copy available in the File.

  
(Lalrinpuii Hrahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04. 2019


  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

Dated 26/4/ 2019

श्री सुशिल कुमार सरोज ने अपील अपील प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 28.09.2018 को सार की है। वर्तमान मामले में, दर्ज किए गए से मुझे पता चलता है कि मुख्य बोर्ड ने पहले से ही लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर कानून का एक आदेश है। 28.09.2018 जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सीनियरिटी नियम, 1937 के नियम 14 (1) के तहत उसके द्वारा सीनियरिटी के प्रयोग ने वही पारित किया गया है, जो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश की सजा होने पर प्रयोग की जाने वाली शक्ति है जोई द्वारा क्योंकि जब सजा का आदेश बोर्ड द्वारा पारित नहीं किया जाता है, लेकिन छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा तब प्रथम अपीलीय प्राधिकारी छावनी बोर्ड होता है और इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय मुख्य अपीलीय प्राधिकारी होता है। Shri Sushil Kumar Saroj appears to have filed his Appeal before the Appellate Authority on 28.09.2018. In the present case, from the recorded I find that there is already an order of Lt. General Officer Commanding in Chief dt. 28.09.2018 in which it is mentioned that the same has been passed in exercise of power vested in him under Rule 14(1) of CFSR Rules, 1937 which is a power to be exercised by the Appellate Authority when the order is punishment is made by the Board because when the order of punishment is not passed by the Board but by the Chief Executive officer of the Cantonment Board then the First Appellate Authority is the Cantonment Board and against the order the Officer Commanding in Chief is the Second Appellate Authority.

हालांकि, अपील के बाद से जो अधिकारी कमांडिंग इन चीफ के सामने पसंद किया गया था, उसे दया अपील का नाम दिया गया क्योंकि यह वैधानिक रूप से एक उचित और सक्षम अपील नहीं थी। इस प्रकार, यह कानून की नजर में कोई अपील नहीं कहा जा सकता है। उस अपील में भले ही अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है, लेकिन यह एक उचित अपील

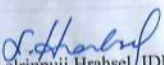
  
(J. J. Hahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment  
Dated 26.04. 2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment  
Dated 26/4/ 2019




के रास्ते में नहीं आ सकता है। However, since the Appeal which was preferred before the Officer Commanding in Chief was given the name of mercy Appeal because it was not a proper and competent appeal, as per the Statute. Thus, it can be said to be no Appeal in the eyes of law. Even though in that Appeal finding has been recorded by the Appellate Authority but that cannot come in the way of a proper Appeal.

अब श्री सुशील कुमार सरोज द्वारा दायर अपील पर रोक लगा दी गई है क्योंकि अपील आधार के आधार पर छावनी बोर्ड के सीईओ के आदेश के आधार पर बनाए रखने के 30 दिनों के भीतर की गई है। वर्तमान मामला में, सजा का आदेश 05.11.2016 को पारित किया गया था, इसलिए, यह निराशाजनक रूप से सीमित है। हालाँकि, चूंकि एनसीएससी द्वारा जारी आदेश है कि याचिकाकर्ता उचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपनी अपील दायर कर सकता है, अपीलीय प्राधिकारी अपील को बिना किसी पक्षपात के विचार कर सकता है। हालाँकि, आयोग के पास देरी को रोकने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए यह अपील पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण यानी दानापुर छावनी बोर्ड पर निर्भर है और यदि यह पाया जाता है कि श्री सुशील कुमार सरोज द्वारा दायर की गई मूल अपील सांविधिक समय तब यह इस आधार पर देरी की निंदा कर सकता है कि उक्त कर्मचारी गलत तरीके से फोरम के समक्ष अपना उपाय कर रहा था। यह रिकॉर्ड से प्रतीत होता है कि सजा के आदेश के खिलाफ श्री सुशील कुमार सरोज 04.11.2016 को जो उनसे संवाद किया गया था, उन्होंने 09.12.2016 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, मध्य कमान, लखनऊ के समक्ष अपील की। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अपील समय में दायर की गई थी, इसलिए तकनीकी पर जाने के बजाय बोर्ड, जो कि उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी है, योग्यता के आधार पर श्री सुशील कुमार सरोज की अपील पर विचार कर सकता है और उन्हें पूरा अवसर प्रदान करने के लिए

  
(Lalrinpuii Hrahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04.2019

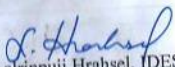
  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment


Dated 26/4/2019

मैं यह स्वीकार कर सकता हूँ कि बोर्ड को कानूनी मुद्दे पर स्पष्ट होना चाहिए कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई / विभागीय कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने में कोई कानूनी रोक नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि कर्मचारी आपराधिक अभियोजन का सामना कर रहा है जिसमें

(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment  
Dated 28/4/2019

चार्जशीट प्रस्तुत की गई है या नहीं क्योंकि दोनों कार्यवाही अलग-अलग पैरामीटर और कुरसी पर चलती रहती हैं और इसलिए दोनों एक साथ जारी रह सकते हैं। NCSC के समक्ष सुनवाई के दौरान यह रुख रखा गया कि विभाग की ओर से भी रखा गया था कि DoPT का एक परिपत्र है जो एक कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रहने पर भी विभागीय कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देता है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आधिकारिक रूप से कई मामलों में फैसला सुनाया है कि कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के बावजूद विभागीय कार्यवाही किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई रोक नहीं है। अपीलीय प्राधिकरण जो कि वर्तमान मामले में छावनी बोर्ड है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किसी भी प्राधिकरण के किसी भी आदेश से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार मामले की सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। कानून के अनुसार अपील का फैसला करने से पहले श्री सुशील कुमार सरोज को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना चाहिए। I may opine that the Board must be clear on the legal issue that there is no legal bar in proceeding with the Disciplinary Action/Departmental action by the Administrative Department, irrespective of the fact that the employee is facing criminal prosecution in which charge sheet is submitted or not because both proceedings continue on different parameter and pedestal and therefore both can continue simultaneously. In course of hearing before the NCSC this stand was also put forward on behalf of the Department of Defence Estate that there is a Circular of DoPT which permits continuance of Departmental proceeding even when the criminal proceeding continues against an employee. Further, the Hon'ble Supreme Court has also authoritatively ruled in number of cases that departmental proceeding is no bar against an employee even though when the employee is facing criminal prosecution for an offence. The Appellate Authority which is the Cantonment Board in the present case will be free to hear the case in accordance with law without being influenced by any order of any

  
(Lalrinpuii Hrahsel, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment  
Dated 26.04.2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment  
Dated 26/4/2019



प्रत्येक मामले के मामलेगत, छोटे अब छोटे के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए के अधिकार कुमार सरोज की अपील पर विचार कर सकता है और साथ ही केन्द्रीय के नियम 12 (ए) (4) के तहत सीईओ के आदेश को रद्द करने / खारिज करने के उनके अनुरोध पर भी विचार कर सकता है। फंड बोर्ड इससे, 1937/38 below of the above facts, the Board may now consider the request of Shri Gurash Kumar Saroj for personal hearing before the Board and may also consider to quash/dismiss the order of the CEO Under Rule 12(4) of the Government Fund Servant Rules, 1937.

The Board has decided to allow a personal hearing of Shri Sushil Kumar Saroj before the Board on 16.06.2019 since in the month of May management Board staff are engaged in Lok Sabha Election duty and also the office premises will be used as polling station. Intimation should also be sent to Shri Sushil Kumar Saroj accordingly.

(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

Dated 26/4/2019

EXTENSION OF LEASE AFTER EXPIRY OF FULL TERM IN  
RESPECT OF SURVEY NO.294, DANAPUR CANTONMENT

Harijaputi Hrahse, (IDES)  
Member Secretary  
Haripur Cantonment

Handl 26.04. 2019

(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

Dated 26/4/2019

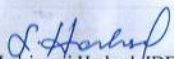
No.11013/2/2016/D(Lands) dated 10.03.2017 and the applicability extended upto 31.12.2018 (1) letter No.11013/2/2016/D(Lands) dated 31.12.2018 (2) Directorate of Defence Estates, Central Command, Lucknow Cantt letter No.57841/Sy.No.294/DNR dated 29.03.2019

2. बोर्ड को संगतगत् किया जाता है कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने अन्तरिम दिशानिर्देश नीति No.11013/2/2016/D(Lands) दिनांक 10 मार्च 2017 द्वारा हस्तगत पट्टे स्थान को निरंतरता की जाए। साथ ही छावनी भू प्रबंधन नियम 1925 और 1937 तथा छावनी पट्टा कोड 1899 और 1912 पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया गति प्रदान की जाए। तदनुसार सर्वे सं० 294 (मकान सं० 26, महाल सं० 3, वार्ड सं० 04) दानपुर छावनी इस कार्यालय के पत्रांक सं० No.CBD/Sy.No.294/954 दिनांक 28 दिसम्बर 2018 द्वारा इसके नवीनीकरण प्रस्ताव निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी को भेजा गया था। It is intimated to the Government of India, Ministry of Defence has issued interim guidelines vide policy letter No.11013/2/2016/D(Lands) dated 10.03.2017 to regularise the occupation of lease held sites as well as expedite the process of renewal of Cantonment Land Administration Rules, 1925 & 1937 and Cantonment Code Leases of 1899 & 1912 lease. 3. Accordingly a proposal for renewal of lease in respect of Survey No.294 (Holding No.26, M.No.3, W.No.4), Danapur Cantonment was forwarded to the Directorate of Defence Estates, Central Command, Lucknow Cantt vide this office letter No.CBD/Sy.No.294/954 dated 28.12.2018.


4. मामले का संक्षिप्त निम्नानुसार प्रस्तुत है / The brief of the case is furnished as under:

(i) स्थान जो सिविल एरिया में स्थित है, सदर बाजार, एक पट्टा नापित क्षेत्र 1890 sqft. सर्वे सं० 294 सम्मिलित करते हुए, मकान सं० 26, महाल सं० 03, वार्ड सं० 04 की पट्टा शुरुआत दिनांक 08.12.1928 को देवी मिस्त्री दुकान के लिए सूचि VI of CLAR 1925. 30 साल की अवधि के लिए दिया गया। अगस्त 1928 से 31 जुलाई 1958 तक प्रति वर्ष 30/6/- के भुगतान पर किया गया था। A site located in civil area, Sadar Bazar, a lease admeasuring an area 1890 sqft. comprising Survey No.294 bearing Holding No.26, M.No.3, W.No.4 was leased out initially on 08.12.1928 to Debi Mistry for shop in Schedule VI of CLAR 1925 for a term of 30 years w.e.f. 01.08.1928 to 31.07.1958 at the payment of lease rent of Rs.30/6/- per annum.

(ii) जी.एल.आर. के अनुसार, सर्वे सं० 294 को बनवारी मिस्त्री और मदन लाल नियमानुसार विभाजन कथनानुसार अगस्त महिने के लिए 45 No.1941/I-R-2 dt.13.9.45 हस्तांतरित किया गया था। आगे के कथित सम्पत्ति को श्री मदन लाल शर्मा एवं श्रीमति रुक्मीनि देवी को CAC Res. No.11 दिनांक 22.12.1960 दिशम्बर 1960 द्वारा हस्तांतरित किया गया, जैसा की C.B.Res.No.2 dt.04.01.1961. द्वारा सुधार किया गया। As per GLR, Survey No.294 was transferred to Banwari Mistry and Madan Lal Sharma by inheritance vide Dinapore statement for the month of August/45 No.1941/I-R-2 dt.13.9.45. Subsequently the said property was transferred to Shri Madan Lal Sharma & Smt. Rukmini Devi vide CAC Res. No.11 dt.22.12.1960 as amended by C.B.Res.No.2 dt.04.01.1961.

  
(Lalrinpui Hrahse, IDIES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment

Dated 26.04.2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment

Dated 26/4/2019

2019





consider the matter of extension of lease after expiry of full term upto 31.12.2019 as per terms and conditions laid down in new lease policy dated 10.03.2017 and decide accordingly.

बोर्ड के विचार और निर्णय के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज तालिका में रखे जा रहे हैं।

All relevant documents are put on the table for consideration and decision of the board.

**RESOLUTION:** The Board has agreed that extension of lease may be given accordingly as per the interim policy of Govt. of India vide MoD letter No. 11013/2/2016/D(Lands) dtd. 10.03.2017 and MoD letter No. 11013/2/2016/D(Lands) dtd. 31.12.2018 for extension till 31.12.2019. However, before effecting extension and collection/acceptance of occupation charge as per the policy, legal opinion may be obtained from the legal advisor as to whether the same can be effected and occupation charge collected in the name of applicants/current occupier.

  
(Lalrinpuoi Hrahse, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment  
Dated 26.04 2019

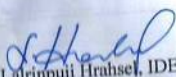
  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment  
Dated 26/4/2019


कार्यसूची सं०-80  
AGENDA NO. 80  
Subject:

**EXTENSION OF LEASE AFTER EXPIRY OF FULL TERM IN  
RESPECT OF SURVEY NO.322-416, HOUSE NO.20, MAHAL No.1,  
WARD NO.4, SADAR BAZAR, DANAPUR CANTONMENT**

संदर्भित (1) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नीति पत्र सं० 11013/2/2016/D(Lands) दिनांक 10 मार्च 2017 और तदनुसंग विस्तार दिनांक 31 दिसम्बर 2019 पत्रांक 11013/2/2016/D(Lands) दिनांक 31 दिसम्बर 2018 द्वारा (2) निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ छावनी पत्रांक सं० 57841/Sy.No.294/D(Lands) दिनांक 29 मार्च 2019 Reference (1) Government of India, Ministry of Defence policy letter No.11013/2/2016/D(Lands) dated 10.03.2017 and the applicability extended upto 31.12.2019 vide

38 | Page

  
(Lalrinpuoi Hrahse, IDES)  
Member Secretary  
Danapur Cantonment  
Dated 26.04. 2019

  
(Brig. A.K. Yadav)  
President  
Danapur Cantonment  
Dated 26/4/2019